साप्ताहिक
डाक पंजीयनः म.प्र./भोपाल/4-479/2019-21
RNI-MPHIN/2015/72544

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

भोपाल, सोमवार, 15 मार्च 2021, वर्ष-6, अंक-50
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना से एक साथ प्रकाशित
पृष्ठ :-8, मूल्य :- 8 रुपए

चौपाल से भोपाल तक

» प्रदेश में 135 लाख मीट्रिक टन खरीदी का लक्ष्य

मप्र में गेहूं की बंपर पैदावार कृषि कर्मण का फिर दावेदार

» किसान के खाते में आएंगे 26662 करोड़ रुपए

» किसानों के खेत में उगा 66360 करोड़ का गेहूं

» एमएसपी में 26662 करोड़ का गेहूं बेचेंगे मप्र के किसान

अरविंद मिश्र, भोपाल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2022 तक किसानों की आय दोगुना करने का जो लक्ष्य तय किया है, वह मप्र में साकार होता दिख रहा है। प्रदेश की शिवराज सरकार किसानों की उपज को समर्थन मूल्य पर खरीद कर उन्हें मालामाल कर रही है। इस बार मप्र में गेहूं की बंपर पैदावार होने की संभावना है। ऐसे में फिर मप्र कृषि कर्मण अवार्ड का दावेदार हो गया है।

दरअसल, मप्र में सरकार कुछ जिलों में 27 मार्च को तो कुछ में 1 अप्रैल से समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदेगी। इस वर्ष गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल है। कृषि विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में इस साल 336 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होगा। एमएसपी के हिसाब से इस बार किसानों के खेतों में करीब 66360 करोड़ का गेहूं पैदा होगा। सरकार इस बार 135 लाख मीट्रिक टन गेहूं किसानों से खरीदेगी। यानी किसानों से सरकार 26662 करोड़ का गेहूं खरीदेगी। गत वर्ष गेहूं उत्पादन के क्षेत्र में मप्र ने देश में सारे रिकॉर्ड तोड़कर 1,29,28000 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की। वहीं गेहूं खरीदी के लिए 14.48 लाख किसानों को 27,000 करोड़ का भुगतान भी किया।

इस साल सबसे अधिक खरीदी मप्र में

देशभर में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। केंद्र का अनुमान है कि मौजूदा खरीद वर्ष में पिछले साल (389.93 लाख मीट्रिक टन) की अपेक्षा 9.56 फीसदी अधिक गेहूं की खरीदी होगी। इस बार भी सबसे ज्यादा गेहूं की खरीद मप्र से होने का अनुमान है। जबकि दूसरे नंबर पर पंजाब होगा।

राज्य	अनुमानित खरीद (लाख मीट्रिक टन)
मध्य प्रदेश	135.00
पंजाब	130.00
हरियाणा	80.00
उत्तर प्रदेश	55.00
राजस्थान	22.00
उत्तराखंड	2.20
गुजरात	1.5
बिहार	1.00
हिमाचल	0.06
महाराष्ट्र	0.003
दिल्ली	0.50
जम्मू	0.10
कुल	427.363

काला गेहूं बन गया सोना

मप्र में इस बार किसानों ने बड़े स्तर पर काले गेहूं की खेती की है। किसानों के लिए काले गेहूं की खेती फायदे का सौदा साबित हो रही है। बाजार में सामान्य गेहूं 1800 से 1900 रु. क्विंटल मिलता है, जबकि बाजार में सामान्य तौर पर काले गेहूं के दाम 4000 से 5000 रुपए प्रति क्विंटल तक मिल जाते हैं। इसलिए काला गेहूं किसानों के लिए सोना बन गया है। उधर, मप्र गेहूं उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया और किसानों को उपार्जन केन्द्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केंद्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई। गेहूं, धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन की 33 हजार करोड़ राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई।

इनका कहना है

सरकार का सबसे अधिक फोकस खेती-किसानी पर है। इसलिए हमने खेती को लाभ का धंधा बनाने का संकल्प लिया है, जो अब मप्र में साकार होगा दिख रहा है। प्रदेश में पिछले एक दशक से लगातार गेहूं सहित अन्य फसलों का उत्पादन बढ़ रहा है। सरकार की कोशिश है कि वह किसानों की अधिक से अधिक उपज को समर्थन मूल्य पर खरीदे।

शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री

मप्र सरकार किसानों के साथ हमेशा रही है। इसलिए यहां के किसानों के लिए ऐसी योजनाएं बनी हैं जिससे किसान लाभान्वित हो रहे हैं। मप्र का गेहूं उच्च किस्म का होता है इसलिए उसकी मांग बढ़ रही है। पंजाब का गेहूं इतना घटिया किस्म का है कि कोई खरीदने को तैयार नहीं है। पंजाब के नाम की कोई रोटी नहीं खाता, क्योंकि पेस्टीसाइड की वजह से वहां की मिट्टी जहरीली है।

कमल पटेल, कृषि मंत्री, मप्र

किसानों को मिलेगा ब्याज मुक्त लोन

- कैबिनेट ने दी राहतः कृषि उपकरणों की खरीद पर लगेगा सिर्फ एक फीसद टैक्स
- जीरो प्रतिशत ब्याज पर मिलने वाले लोन के लिए 1 हजार करोड़ रुपए मंजूर
- किसानों को कृषि उपकरणों पर अधिकतम ढाई लाख रुपए का होगा फायदा
- हार्वेस्टर व ट्रेक्टर पर अब दस की जगह मात्र एक फीसद लगेगा मोटरयान कर
- समर्थन पर खरीदा 6.45 लाख टन गेहूं नागरिक आपूर्ति निगम करेगा नीलाम

भोपाल। मध्यप्रदेश में कृषि उपकरणों की खरीद पर अब सिर्फ एक फीसदी टैक्स लगेगा। यह अभी 10 प्रतिशत तक लगता था। इससे किसानों को अधिकतम ढाई लाख रुपए तक का फायदा होगा। यह फैसला शिवराज कैबिनेट ने लिया है। साथ ही कृषि साख सहकारी संस्थाओं के माध्यम से किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ही अल्पावधि फसल ऋण मिलेगा। इसके लिए 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को एक और राहत देते हुए फैसला किया है कि ट्रैक्टर और हार्वेस्टर पर लगने वाले मोटर वाहन टैक्स लगने की अवधि दो साल के लिए बढ़ा दी गई है। वहीं, 2019-20 में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 6.45 लाख टन गेहूं को नीलाम करने का निर्णय भी लिया गया। नीलामी की प्रक्रिया मध्य प्रदेश नागरिक आपूर्ति निगम ई-ऑक्शन प्रक्रिया के माध्यम से करेगा। दरों के संबंध में निर्णय मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली समिति लेगी। खरीफ फसलों के लिए ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 28 मार्च और रबी सीजन के लिए 15 जून 2021 रहेगी।

प्राधिकरणों का ब्याज माफः भोपाल, इंदौर, जबलपुर देवास, ग्वालियर और उज्जैन विकास प्राधिकरण को नगर तथा ग्राम निवेश के माध्यम से दिए गए लोन पर अभी अधिरोपित ब्याज एवं दांडिक ब्याज की राशि 12 करोड़ को माफ किया जाएगा।

इनका कहना है

किसानों को सहूलियत देने अहम निर्णय लिए गए हैं। प्रदेश में पंजीकृत कंबाइन हार्वेस्टर और ट्रेक्टर पर जीवनकाल कर एक प्रतिशत ही लिया जाएगा। किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण 2020-21 में भी देना जारी रहेगा। किसानों से वर्ष 2019-20 में समर्थन मूल्य पर खरीदे गए 73.70 लाख टन गेहूं में से 6.45 लाख टन को राज्य सरकार नीलाम करेगी।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, गृह मंत्री, मप्र

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाह बोले

बिचौलियों की टूटेगी चेन और किसान बनेंगे आत्मनिर्भर

भोपाल। मध्यप्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में किसानों की अहम भूमिका होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान को साकार करने में उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग जुटा हुआ है। मौसम से किसानों की फसल खराब होती है, तो उसका मुआवजा किसानों को सीधे तौर पर मिले। कोल्ड स्टोरेज लाभ किसान ले सकें, इसके लिए अनुदान व्यवस्था है, इससे पूरे परिवार को रोजगार मिलेगा। परिवार को रोजगार मिलेगा तो किसान आत्मनिर्भर होंगे। किसान फसल का ज्यादा उत्पादन कर सकेंगे। वहीं सुरक्षित रखकर बाजार में बेच भी सकेंगे। इससे बिचौलियों की चेन टूटेगी और आत्मनिर्भर भी बनेंगे। यह बात प्रदेश के उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भरतसिंह कुशवाह ने एक खास बातचीत में कही। **-बातचीत के मुख्य अंशः**

सवालः आत्मनिर्भर मप्र को सफल बनाने के लिए आपके विभाग की क्या योजना?

जवाब: इसे सफल बनाने के लिए एक जिला एक उत्पाद कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। इससे जिले की पहचान बढ़ेगी और जो भी व्यापारी अन्य प्रांतों से प्रदेश में आते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए कि किस जिले में किस चीज का उत्पादन हो रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि प्रधानमंत्री ने जो आह्वान किया है कि छोटे-छोटे उद्योग हैं एक जिला एक उत्पादन के तहत हर एक जिले में एक फूड प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना हो सके। इससे एक जिले में उत्पादन के हिसाब से फूड प्रोसेसिंग यूनिट की शुरुआत हो सकेगी।

सवालः संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए आपका विभाग क्या प्रयास करेगा?

जवाब: मौसम आधारित प्रश्नों के लिए सरकार के द्वारा फसलों का बीमा कराया जा रहा है। इस बार हमने बीमा के लिए जो प्रयास किया था उसमें बार-बार जो टेंडर री कॉल हुए और समय पर जो कंपनियां उसमें भाग नहीं ले पाई। इसमें मुख्यमंत्री ने चिंता जाहिर करते हुए आरबीसी में जो प्रावधान है उसको लागू किया है कि अगर मौसम के कारण हमारे किसान भाइयों की फसल खराब होती है तो उनका मुआवजा किसानों को सीधे तौर पर मिलना चाहिए।

सवालः सीएम ने सब्जियों की एमएसपी तय करने की बात कही थी, क्या तैयारी है?

जवाब: मुख्यमंत्री किसान पुत्र हैं। उन्हें किसानों की हर हमेशा चिंता रहती है। यह सही बात है कि ज्यादातर शिकायतें हमारे कच्चे उत्पादन को लेकर मिलती थीं। कई बार उत्पादन अधिक होने से बाजार में भाव गिर जाते थे और कच्चे उत्पादन का किसान ज्यादा समय तक नहीं रख सकता है। एक से 2 दिन तक ही कच्चे उत्पादन को रखा जा सकता है। अगर 2 दिन में भाव सही नहीं मिलता था तो किसान मजबूर हो जाता था। ओने-पौने दामों में अपने उत्पादन को बेचने के लिए। इसलिए सीएम के निर्देशानुसार हमने स्थाई व्यवस्था करने के लिए एक रोडमैप तैयार किया है, जिसमें हमने कच्चे उत्पादन को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की चैन को बढ़ाया है। भंडारण की चैन को भी बढ़ाया है जिससे कच्चे उत्पादन को ज्यादा लंबे समय तक किसान उस उत्पादन को सुरक्षित रख सकें और जब भी मंडी में अच्छे भाव हों तब वह अपने उत्पादन को बेच सकें।

सवालः सूखी सब्जी का प्रचलन बढ़ा है, उसको लेकर विभाग क्या करेगा?

जवाब: प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने यह संकल्प लिया है कि हमारा किसान आत्मनिर्भर बनें। हमारे किसानों की आय दोगुनी हो। जब किसान आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा मप्र आत्मनिर्भर बनेगा। मप्र आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा। इसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री ने फूड प्रोसेसिंग के काम को जमीनी स्तर तक नीचे तक उतारने के लिए जो बजट में प्रावधान किया है। मध्य प्रदेश में पहली बार कच्चे उत्पादन ओं का प्रोसेसिंग होगी। उस प्रोसेसिंग के माध्यम से किसानों को जो आय होगी, इसके पीछे सरकार की सोच यह है कि किसान सिर्फ उत्पादन ना करें, बल्कि उससे किसान बाजार को भी अपने हाथ में ले सकें, इसलिए किसानों के उत्पादन की प्रोसेसिंग वह खुद कर सकें, जो प्रोसेसिंग की इकाई है उसके लिए अनुदान देने का प्रावधान भी है।

विकास की राह पर ग्राम पंचायत जनकपुर

जल संरक्षण, स्वच्छता, सौंदर्यीकरण और सड़क से बदली गांव की तस्वीर

संवाददाता, केसली

ग्राम पंचायत जनकपुर के बीचों-बीच से निकला नाला स्थानीय निवासियों के लिए हमेशा से ही सिरदर्द बना हुआ था। इस समस्या को लेकर सैकड़ों बार शासन-प्रशासन से गुहार लगा चुके ग्रामीणों को अब जाकर राहत मिली है। ग्राम पंचायत के प्रयास व जनपद पंचायत के सहयोग से हाल ही में नाले के सामुघाट पर रपटा का निर्माण कार्य पूरा किया गया है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव के बीचों-बीच नाला होने से बरसात और उसके बाद भी नाले में पर्याप्त जल भराव होने से ठंड के चार माह भी आने-जाने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता था।

समस्या से निजात पाने के लिए कई बार प्रयास किए गए, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। इसी बीच क्षेत्र के दौरे पर आए केसली जनपद अध्यक्ष अतुल भाई डेवाड़िया से ग्रामीणों ने इस समस्या को हल कराने की मांग की। ग्रामीणों को समस्या से निजात दिलाने के लिए जनपद अध्यक्ष की ओर से स्वीकृत की गई 14 लाख 83 हजार की राशि से नाले पर पुलिया का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। सरपंच राजेन्द्र सिंह लोधी को भी अपने कार्यकाल में नाले पर पुलिया और गांव की आंतरिक सड़कों का निर्माण कराना ही सबसे बड़ी चुनौती साबित हुई। हालांकि उन्होंने इन दोनों समस्याओं को केसली जनपद पंचायत व ग्रामीणों के सहयोग से हल करने में सफलता हासिल कर ली।

स्वच्छता की ओर बढ़ रहा गांव

किसी भी गांव के विकास में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए गांव में होने वाले सामुहिक व निजी कार्यक्रमों के दौरान फैलने वाली गंदगी व इससे होने वाली परेशानियों से बचने के लिए 3 लाख 75 हजार की लागत से स्वच्छता परिसर के साथ ही 12 लाख की लागत से एक सामुदायिक भवन का निर्माण करवाए जाने की जानकारी पंचायत सचिव बहादुर सिंह लोधी ने दी। सौंदर्यीकरण के उद्देश्य से अतुल भाई डेवाड़िया ने अपनी जनपद निधि से हरसिद्धि माता मंदिर में 50 हजार रुपए के कार्यों को मंजूरी दी है। साथ 11 हजार रुपए निजि तौर पर भी दान दिए हैं। पुलिया भूमि पूजन के दौरान महिलाओं से पानी की समस्या सुनकर उन्होंने हैंडपंप भी स्वीकृत किया था।

इनका कहना है

पंचायत की ओर से जल संरक्षण के लक्ष्य को लेकर जल स्रोतों के आसपास रिचार्ज सिस्टम भी बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही खेत तालाब, वृद्धावस्था पेंशन, आवास योजना सहित अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है।

पूजा जैन, सीईओ, जनपद पंचायत

गांव में पक्की सड़कें नहीं होने से वाहन चालकों के साथ ही पैदल चलने में भी परेशानी होती थी। ऐसे में जनपद ने सुदूर सड़क निर्माण योजना के माध्यम से मुख्य मार्ग से पड़रई मार्ग तक 14 लाख 35 हजार की लागत से इसी वर्ष सड़क का निर्माण कराया है। वहीं दूसरी ओर 13 लाख 55 हजार की राशि से सामुदायिक भवन से शांतिधाम मोतन तक जाने वाली सड़क का निर्माण कार्य भी करवाया गया है।

राजेन्द्र सिंह लोधी, सरपंच

वर्ष 2020-21 में नवीन शांतिधाम के पास 6 लाख सात हजार की राशि से जनपद पंचायत की ओर से मंजूर, एक जलाशय और इसके अलावा निर्मल नीर योजना के माध्यम से एक कुंआ का निर्माण कार्य कराया गया है। तालाब बनने से कृषि भूमि का सिंचाई रकवा बढ़ गया है। बरियाघाट में सिंचाई क्षेत्र बढ़ाने के लिए 12 लाख की लागत से एक स्टापडेम बनाने की मंजूरी भी अतुल भाई डेवाड़िया ने प्रदान की थी। इस स्टापडेम का लाभ वर्तमान में 25 किसान ले रहें हैं और इससे 23 हेक्टेयर रकवा सिंचित किया गया है।

भरत सिंह लोधी, रोजगार सहायक

दतिया की रेखा को कड़कनाथ के 15 चूजों ने कर दिया मालामाल

- आज 70 मुर्गे की मालकिन, एक की कीमत ढाई हजार रुपए
- कड़कनाथ व अंग्रेजी सूकर बेचकर इम्युनिटी पावर को बढ़ाया

संवाददाता, दतिया

जिले के झड़िया गांव की रेखा महरोली ने जहां एक ओर कोरोना काल में कड़कनाथ और अंग्रेजी सूकर बेचकर लोगों का इम्युनिटी पावर को बढ़ाया। दूसरी ओर खुद के परिवार को भी आर्थिक मजबूती दी। कुल 15 कड़कनाथ के चूजों से 1 साल पहले अपने व्यवसाय की शुरुआत की थी। इसके बाद उनका यह व्यवसाय फलीभूत होता गया। उन्होंने अंग्रेजी सूकर का भी पालन शुरू कर दिया। एक ओर जहां लोगों का इम्युनिटी सिस्टम मजबूत होने लगा। वहीं रेखा के परिवार को भी आर्थिक मजबूती मिलती चली गई। यह मामला झड़िया का है, जहां 40 वर्षीय रेखा महरोलिया ने एक सरकारी मदद से कड़कनाथ के कुछ चूजे लिए और उनकी देखभाल की। इसके लिए एक स्वयं सहायता समूह ने भी उनकी मदद की थी। देखते ही देखते कड़कनाथ का कुनबा 60 से 70 मुर्गे मुर्गियों तक पहुंच गया। कोरोना काल में कड़कनाथ के मुर्गे की मांग इम्युनिटी बढ़ाने में सौ फीसद कारगर होने के कारण बढ़ गई। इसके चलते रेखा का एक-एक कड़कनाथ मुर्गा दो से ढाई हजार रुपए में बिकने लगा। यहां तक कि लोग उनके गांव व घर तक भी पहुंचने लगे। इससे उत्साहित होकर उसको कृषि विज्ञान केंद्र के कुछ वैज्ञानिकों ने सलाह दी कि अंग्रेजी सूकर को भी पालने से और भी ज्यादा लाभ मिलेगा। अंग्रेजी सूकर की मांग विदेशों व पांच सितारा होटलों में भी काफी है। बस फिर क्या था। रेखा ने अंग्रेजी सूकर भी पालना शुरू कर दिया। अब वह इस इलाके में इम्युनिटी बढ़ाने का ब्रांड बन गई। हर कोई बड़ा ग्राहक इम्युनिटी का मुकाम ढूंढते हुए रेखा के यहां पहुंचने लगा है। कड़कनाथ और अंग्रेजी सूकर खरीदने वाले यहां बने रहते हैं। हाल ही में उसने एक अंग्रेजी सूकर एक प्रसिद्ध होटल के लिए 18 हजार में बेचा है।

बढ़ाना चाहती हैं सूकर का कुनबा

रेखा महोरोलिया बताती हैं कि मुर्गे मुर्गियों की कड़कनाथ प्रजाति तो उसके यहां बढ़िया से फलीभूत हो रही है। इसके पहले वह दूसरों के खेतों में मजदूरी करने जाती थीं। इस काम के बाद अब वह प्रतिमाह 10 से 15 हजार रुपए कमा रही है। इस आय में से खुद के परिवार व अंग्रेजी सूकर पालने में खर्च हो जाते हैं। यदि उसे दो लाख रु. तक के लोन की मदद मिल जाए, तो अंग्रेजी सूकर के लिए भी एक बड़ा कुनबा बनवाकर उस योजना को भी सफल कर सकती हैं। अभी गांव तक अंग्रेजी सूकर के खरीदार पहुंच रहे हैं, पर वह उनकी आपूर्ति नहीं कर पा रही है, क्योंकि अंग्रेजी सूकर की संख्या काफी कम है।

इनका कहना है

रेखा व उसके पति को प्रारंभिक तौर पर कुछ कड़कनाथ के कुछ चूजे दिलवाए गए थे, जो बेहतर पालन पोषण से कड़कनाथ प्रजाति खूब फलफूल गई और इन कड़कनाथ की लोगों में भी खूब डिमांड रही। अंग्रेजी सूकर प्रोजेक्ट के लिए भी व्यवस्था की जा रही है।

डॉ. अजय अहिरवार, पशु चिकित्सक, दतिया

गांव की दो महिलाओं ने नहीं कटने दिया एक भी पेड़

हिम्मत बांधी, हार नहीं मानी और उगा दिया घनघोर जंगल

जावेद अली, मंडला

हम और आप शायद पूरी जिंदगी में दस पेड़ भी नहीं लगा पाते होंगे। हमें पर्यावरण की चिंता तो है, लेकिन, उसे बचाने के रास्ते पर चलने की हमारी हिम्मत नहीं होती। लेकिन, कुछ महिलाएं ऐसी हैं, जो न केवल पेड़ लगा रही हैं, बल्कि उन्होंने पूरा का पूरा जंगल ही उगा दिया है। जागत गांव हमार अपने इस अंक में मंडला जिले के मनेरी गांव की कल्लो बाई और शालिनी के बारे में बता रहा है। ये दोनों पर्यावरण से इतना प्यार करती हैं कि इन्होंने 200 हेक्टेयर का घनघोर जंगल ही उगा दिया है। इन्होंने यहां करीब 2.50 लाख पेड़-पौधे लगा दिए। इनके मन में पल-पल ये सवाल उठता है कि अगर जंगल खत्म हो जाएंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी।

संघर्ष भरा जीवन

कल्लो बाई और शालिनी का जीवन संघर्ष से भरा है। कुछ साल पहले मनेरी के पास गोराम बाबा की पहाड़ी पर घनघोर जंगल हुआ करता था। लेकिन, ये पहाड़ी मंडला जिले में ऐसी जगह है, जहां अधिकांश लोग आज भी खाना बनाने के लिए चूल्हे का उपयोग करते हैं। चूल्हे पर खाना बनाने की वजह से लोग इसी पहाड़ी से लकड़ियां काटकर ले जाते थे। हालात यहां तक पहुंच गए कि पूरा का पूरा जंगल साफ हो गया। इन दोनों महिलाओं से ये देखा न गया। उनके मन में फिर वही सवाल था कि जंगल में पेड़ नहीं बचेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी को क्या मिलेगा।

गांव वालों का नहीं मिला सहयोग

इस सोच के साथ दोनों ने पौध रोपण शुरू किया। ये काम इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि, पौधा रोपण के दौरान महिलाओं को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ा। सबसे बड़ी दिक्कत थी पूरे गांव की। गांव के लोग जंगल काटने पर उतारू थे। यहां तक कि दोनों पर झूठा मामला भी दर्ज करवा दिया गया। लेकिन, दोनों महिलाओं ने हिम्मत नहीं हारी और एक भी पेड़ को कटने नहीं दिया। इस वीरान पहाड़ी पर करीब 2.50 लाख पेड़-पौधे हैं। दोनों ने मिलकर पहाड़ी पर सागौन, साल, हर्रा, आंवला, बेल जैसे घने, छायादार कीमती पेड़ लगा दिए। अभी ये पेड़ 30 से 50 सेंमी मोटाई के हैं।

बे-मौसम बारिश-ओले, किसानों की मेहनत चौपट

कमलनाथ ने कहा- राहत दे सरकार, सीएम शिवराज बोले- टेंशन नहीं, मैं हूं न

अलर्ट
प्रदेश में फिर बिगड़ेगा मौसम का मिजाज

संवाददाता, भोपाल

मध्यप्रदेश में मार्च महीने में हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसल चौपट हो गई है। कई जिले इससे प्रभावित हुए हैं। इसी सिलसिले में पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने राज्य सरकार से किसानों को राहत देने की मांग की है। कमलनाथ ने अपने ट्वीट में कहा है कि बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को जो नुकसान हुआ है, राज्य सरकार उन्हें राहत दे। गौरतलब है कि कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। किसान पहले से ही परेशानी के दौर में गुजर रहा है, ऐसे में इस प्राकृतिक आपदा से उसे और संकट का सामना करना पड़ेगा। सरकार तत्काल किसान भाइयों को राहत देना प्रारंभ करें। सरकार ने कहा है कि किसानों को हर संभव मदद करेंगे।

यहां हुई ओलावृष्टि

मध्यप्रदेश के कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि हुई है। इनमें भोपाल, जिले समेत सागर, रीवा, श्योपुर, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, खरगोन, नीमच, सिवनी, छिंदवाड़ा और दमोह जिले में बारिश और आंधी चली। कई जिलों में ओलावृष्टि भी हुई। इस कारण किसानों को काफी फसल खराब हो गई। फसलों को भारी नुकसानइस सीजन की प्रमुख गेहूं की फसल पूरी तरह पक चुकी है। अधिकांश स्थानों पर खेतों में कटाई चल रही है। ऐसी स्थित में बरसात और ओले गिरने के कारण फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा आम की फसल भी तबाह होने लगी है।

मिलेगा उचित मुआवजा

इधर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी एक बयान आया है। चौहान ने कहा कि कि किसान भाइयों को मैं कहना चाहता हूं कि वे फिक्र न करें, मैं किसलिए हूं। परेशान होने की जरूरत नहीं है।

जनती फसलें बर्बाद हो गई है, उन्हें उचित मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने भी कहा है कि किसानों का संकट सरकार का संकट है। यह किसानों की सरकार है। किसानों को राहत देंगे।

18 से बारिश का फिर दौर

फरवरी माह के मध्य से ही लगातार पश्चिमी विक्षोभ के उत्तर भारत पहुंचने का सिलसिला बना हुआ है। इनकी वजह से मार्च माह की शुरुआत में जहां गर्मी के तीखे तेवर देखने को मिले, वहीं अब बेमौसम बारिश और ओला वृष्टि ने किसानों की मुसीबत बढ़ा दी है। मौसम विज्ञानियों का दावा है कि 18 मार्च से आंधी-पानी का एक और दौर शुरू हो सकता है।

'सरकार' जब फंड नहीं था तो लावारिस ही रहने देते गौमाता

भोपाल की गौशालाओं में एक ही शेड के नीचे बीमार व स्वस्थ गाय

» अनदेखी से न पीने का पानी और न चारा, 1 साल में 650 की मौत

» भोपाल में अभी 12 गौशालाएं बनकर तैयार हैं और 30 नई बनेंगी

» 33 गौशालाओं में किसी की छत टूट रही तो कहीं दो दिन का भूसा

संवाददाता, भोपाल

प्रदेश में एक हजार सरकारी गौशालाएं बन चुकी हैं और दो हजार से ज्यादा नई गौशालाएं बनाने की घोषणा बजट में सरकार कर चुकी है। भोपाल में 12 गौशालाएं बनकर तैयार हैं और इनमें से हरेक पर 25 से 27 लाख रुपए खर्च हुए हैं। 30 गौशालाएं और बनना है। लेकिन, ये सब सिर्फ सरकारी आंकड़े हैं। गौशालाओं की दुर्दशा वो तस्वीर अभी भी रिकॉर्ड से गायब है, जो डरावनी है। दरअसल, भोपाल में अभी 21 अशासकीय और 12 सरकारी गौशालाएं संचालित हो रही हैं। इनमें 6500 गाय हैं। इन्हीं में से बीते एक साल में 650 गायों की मौत हो चुकी है। इनकी मौत की वजह गौशालाओं में साफ-सफाई न होना, बीमार और स्वस्थ गायों को एक ही शेड में रखना है। न तो अफसर यहां नियमित दौरा करते हैं और न ही गायों को अच्छा चारा-भूसा दिया जा रहा।

बजट चाहिए 150 करोड़

पिछले दिनों पशुपालन विभाग ने सरकार से गौशालाओं के संचालन के लिए 150 करोड़ रुपए मांगे थे, लेकिन वित्त विभाग ने सिर्फ 11 करोड़ 80 लाख रुपए ही दिए।

नौ महीने से कुछ नहीं मिला

ज्यादातर गौशालाओं में चारा-भूसा नहीं है, यदि है तो घटिया क्वालिटी का, क्योंकि यहां देखरेख कर रहीं समितियों को प्रशासन से 9 महीने से फंड नहीं मिला। कुछ में दो दिन का ही भूसा है। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा। नगर निगम ने कहा था कि हाट बाजार व मंडियों से निकला हरा चारा भेजेंगे, लेकिन वो साल में एक या दो बार ही पहुंचा। गौ-संवर्धन बोर्ड हर तीन महीने में प्रति गौवंश/दिन 20 रुपए समितियों को देता है।

भोपाल की निजी गौशालाओं को मिला बजट

वर्ष	बजट रुपए में
2017-18	10384073
2018-19	5233375
2019-20	10000056
2020-21	18556800
मुख्यमंत्री गौसेवा योजना	
2020-21	1260000

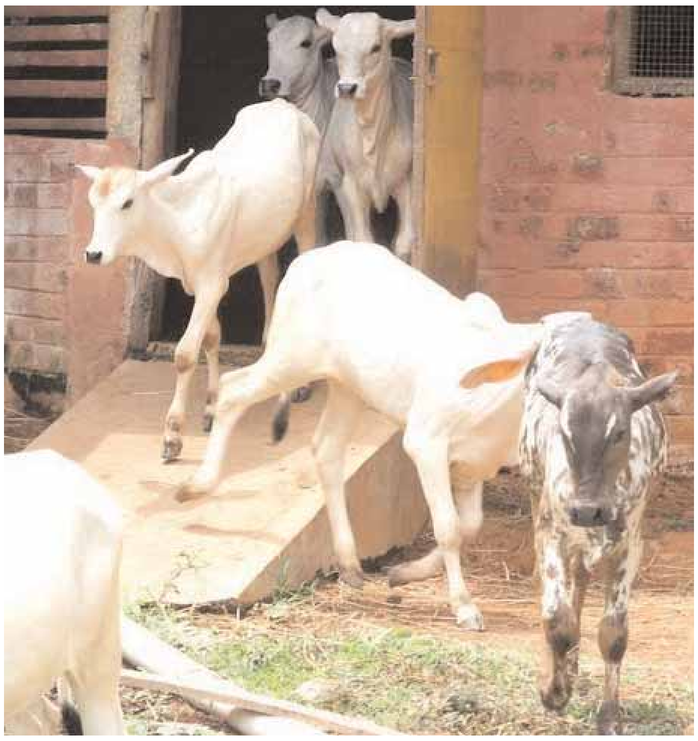

इनका कहना है

विदिशा रोड के जीवदया गौरक्षण केंद्र में 1700 गाय रख सकते हैं, लेकिन यहां 1900 गाय रख दी गई हैं। रखरखाव ठीक से नहीं हो सका तो 300 गाय साल में दम तोड़ चुकी हैं।

■ **अशोक जैन**, सदस्य, जिला गौ-संवर्धन बोर्ड

बजट के लिए कई बार पत्र लिख चुके हैं। नहीं मिला। जून में कुछ मिला था। मरने वाली कई गायें बीमार थीं। हर साल 650 से 1200 गाय मर रही हैं।

■ **अजय रामटेके**, डिप्टी डायरेक्टर, पशुपालन विभाग

गांव अइयापुर तूमड़ा में बनी श्रीकृष्णा गौशाला में यहां सिर्फ दो दिन का भूसा है। तीन महीने से वेतन नहीं मिला। सरपंच जैसे-तैसे पैसे की व्यवस्था कराते हैं। यहां 103 गाय हैं। एक साल में 25 मर चुकी हैं। 4 बार बोर कराया, पर पानी नहीं निकला। एक खेत से पाइप डालकर पानी ले रहे हैं।

■ **दिनेश भिलाला**, कर्मचारी, श्रीकृष्णा गौशाला

मुगालियाछाप गांव की महामृत्युंजय गौशाला को न सरकारी फंड मिल रहा, न अफसर सुन रहे। गौशाला का स्ट्रक्चर खराब हो गया है। छत कभी भी गिर सकता है। गायों को पिलाने के लिए पानी छह किमी दूर से लाते हैं। अफसरों को कई चिट्ठी दीं, पर कोई सुनने वाला नहीं। 10 से 12 गाय मर चुकी हैं।

■ **अरविंद पटेल**, संरक्षक, महामृत्युंजय गौशाला

कुठार गांव की राधाकृष्णा गौशाला चलाने के लिए अपनी जेब से पैसे खर्च कर रहा हूं, क्योंकि 9 महीने से फंड नहीं मिला। 68 गाय दम तोड़ चुकी हैं। सरकार ने गौशाला तो खुलवा दी, लेकिन इसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये नहीं बताया। साफ-सफाई भी नहीं हो पा रही।

■ **मुकेश अहिरवार**, सरपंच, कुठार पंचायत

कोलाहल में ओझल कृषि क्षेत्र में बेहतरीन कदम

वरुण गांधी
सांसद, भाजपा

लोगों को उन सुधारों और कदमों पर गौर करना चाहिए जो मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कर रही है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ समय से जारी चंद किसान संगठनों के विरोध-प्रदर्शन के बीच कई अहम तथ्य कहीं पीछे छूट गए हैं। उन पर गौर करने से वस्तुस्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश केंद्र के हालिया बजट पर भी दृष्टि डाली जाए।

लोगों को उन सुधारों और कदमों पर गौर करना चाहिए जो मोदी सरकार कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कर रही है। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कुछ समय से जारी चंद किसान संगठनों के विरोध-प्रदर्शन के बीच कई अहम तथ्य कहीं पीछे छूट गए हैं। उन पर गौर करने से वस्तुस्थिति को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। इसी कड़ी में वित्त वर्ष 2021-22 के लिए पेश केंद्र के हालिया बजट पर भी दृष्टि डाली जाए। उसमें कृषि के लिए 1.23 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसकी तुलना में 2018-19 में यह आवंटन 57,600 करोड़ रुपए था। वह भी पूर्ववर्ती संप्रग सरकार के 2013-14 के बजट की तुलना में तीन गुना अधिक था। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गहरे जुनून से प्रेरित सरकार शोर-शराबे से दूर किसानों के उत्थान के लिए मदद का दायरा बढ़ा रही है। कृषि इनपुट के मोर्चे पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के असर को समझें। यह योजना जुलाई 2015 में शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य प्रत्येक खेत को पानी उपलब्ध कराया जाना था। साथ ही पानी के इस्तेमाल की समग्र दक्षता में सुधार करना भी इसका मकसद था। इसके लिए मोर क्रॉप पर ड्रॉप जैसा प्रेरक नारा गढ़ा गया। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय में इसके लिए एक मिशन निदेशालय का गठन किया गया।

सिंचाई लाभ कार्यक्रम को जल्दी पूरा करने के लिए 99 से अधिक परियोजनाओं को चिन्हित भी किया गया। परिणामस्वरूप 2019 तक कुल 76 लाख हेक्टेयर भूमि को इससे फायदा मिला। नाबार्ड के दीर्घकालिक सिंचाई कोष के माध्यम से 40,000 करोड़ रुपये की मदद उपलब्ध कराई गई। इसके अलावा इस योजना के तहत माइक्रो-इरिग्रेशनयानी सूक्ष्म सिंचाई पर भी ज्यादा ध्यान दिया गया। इससे सूक्ष्म सिंचाई का क्षेत्र 8.13 लाख हेक्टेयर से बढ़कर करीब 90 लाख हेक्टेयर हो गया। निश्चित रूप से इसका श्रेय सूक्ष्म सिंचाई निधि कोष को जाता है, जिसका बजट हाल में दोगुना कर 5,000 करोड़ रुपये किया गया है। सरकार ने पूरे देश में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी सराहनीय पहल भी की है। इससे किसानों को उनकी उर्वरक इनपुट लागत को कम करने के लिए सालाना प्रति हेक्टेयर औसतन 5,000 रुपये मिले। सरकार जीरो-बजट प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है। आंध्र प्रदेश ने 2024 तक 8 लाख हेक्टेयर भूमि पर शत प्रतिशत जीरो-बजट प्राकृतिक खेती की योजना तैयार की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों का जोखिम कम करने के लिए शुरू की गई है, जिसमें किसान के लिए बहुत कम प्रीमियम भुगतान (फसल के अनुसार तकरीबन 1.5-2 प्रतिशत) तय किया गया है। इसके चलते खरीफ फसल के लिए बीमा कवरेज में 2.72 करोड़ हेक्टेयर से 3.75 करोड़ हेक्टेयर की उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई। ऐसी ही बढ़ोतरी समग्र बीमा राशि में भी हुई। फसल की अच्छी कीमत दिलाने के लिए मोदी सरकार ने ई-नाम (ई-नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट) योजना के माध्यम से कृषि मार्केटिंग में सुधार के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया। इसके जरिये खरीदार देश की किसी भी मंडी से कोई भी कृषि-उपज खरीद सकते हैं। साल 2020 की शुरुआत तक 18 राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों की तकरीबन एक हजार कृषि मंडियों को ई-नाम नेटवर्क से जोड़ा जा चुका था। इस साल हजार से ज्यादा और मंडियों को ई-नाम से जोड़ा जाना है। दूसरी तरफ, अब एपीएमसी या कृषि मंडी अपने बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए कृषि इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड से भी मदद हासिल कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त ग्रामीण बुनियादी ढांचा फंड के लिए आवंटन 30,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 40,000 करोड़ कर दिया गया है। पिछले बजट में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत किसान रेल की शुरुआत भी ऐसा ही एक कदम है, जिसका स्वागत किया जाना चाहिए। यह कृषि उपज के लिए कोल्ड चेन बनाने में बहुत मददगार होगी। किसानों को बाजार की प्रतिस्पर्धा का सामना करने में समर्थ बनाने के लिए सरकार अगले पांच वर्षों में 10,000 से ज्यादा नए किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) बनाने पर जोर दे रही है। ऐसे संगठनों को सरकार का समर्थन उन्हें बाजार में बेहतर शर्तों पर मोलभाव की क्षमता प्रदान करेगा, जबकि फाइनेंसिंग उन्हें बाजार की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करेगी। न्यूनतम समर्थन मूल्य के मामले में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को फायदा पहुंचाने के लिए कई कदम उठाए हैं। उदाहरण के लिए, सरकार ने 2019-20 में खरीफ और रबी फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाया ताकि इन फसलों के लिए राष्ट्र स्तर पर आकलित औसत उत्पादन लागत का तकरीबन 1.5 गुने के स्तर पर पहुंच सके। इसमें गेहूं का ही मामला ले लें, जिसकी एमएसपी 85 रुपए प्रति क्विंटल बढ़ाई गई, जिससे कुल रिटर्न 109 प्रतिशत हो गया। प्रतिशत के लिहाज से ही किसान को पिछले वर्ष की एमएसपी में 4.6 प्रतिशत की बढ़ोतरी मिली। इस आमदनी में इजाफे के लिए सरकार ने 2019 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरू की। इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों को 6,000 रुपए सालाना की मदद दी जाती है। इस योजना में अब देश के सभी किसानों को शामिल कर लिया गया है। वर्ष 2021 में तकरीबन 14 करोड़ किसान परिवारों के लिए 65,000 करोड़ का आवंटन किया गया। इसके अलावा मोदी सरकार ने दूसरे उपायों जैसे कि डेयरी के जरिये किसानों की आमदनी बढ़ाने वाली पहल की है। वर्ष 2025 तक मिल्क प्रोसेसिंग क्षमता 5.35 करोड़ टन से बढ़ाकर 10.8 करोड़ टन करने का लक्ष्य रखा गया है। ऑपरेशन फ्लड (डेयरी विकास कार्यक्रम) की ही तरह ऑपरेशन ग्रीन्स की शुरुआत गेहूं और धान से इतर फसलों की खेती को बढ़ावा देकर देश में कृषि फसलों का संतुलन कायम करने में दूरगामी असर वाली होगी। नए कृषि कानूनों के विरोध प्रदर्शनों पर बहुत अखबारी स्याही खर्च की गई है, लेकिन मोदी सरकार ने किसानों की मदद के लिए जो काम किया है, शायद ही उस पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। काम के इतने व्यापक दायरे को देखते हुए इस विषय पर किसी भी सरकार की आलोचना करना बहुत आसान है। हालांकि विचारशील लोगों को उन बेहतरीन सुधारों और कदमों पर गौर करना चाहिए, जो सरकार भारत के कृषि क्षेत्र को पटरी पर लाने के लिए कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यह सरकार गरीब किसानों की जरूरतों से परिचित है और यह सुनिश्चित करने की गहराई से कोशिश कर रही है कि अगले दशक तक उनकी आमदनी बढ़ जाए।

अब राज्यों के नवाचारों को परखने का समय

संध्या वेंकटेश्वरन
स्वास्थ्य -नीति विशेषज्ञ

हाल-फिलहाल के वर्षों में किसी भी अन्य घटना से कहीं ज्यादा इस महामारी ने जीवन, आजीविका, शिक्षा और स्वास्थ्य को प्रभावित किया है। इस दौर की चुनौतियों से पार पाने के लिए दुनिया भर में नवाचार, यानी इनोवेशन हुए हैं और उनके मुताबिक कुछ तौर-तरीके भी बदले गए हैं, लेकिन इनका लाभ चंद लोगों को ही मिल सका, सभी को नहीं। स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें, तो बेहतर स्वास्थ्य-व्यवहार अपनाने के उपाय, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचों की सीमाएं, मानव संसाधनों की उपलब्धता में कमी और आपूर्ति श्रृंखला में रुकावट जैसी समस्याएं व्यापक तौर पर देखी गई हैं। बेशक ये सभी महामारी की देन नहीं थीं, बल्कि कई तो पहले से हमारे समाज में मौजूद थीं, लेकिन महामारी के दौरान ये सभी समस्याएं कहीं ज्यादा गहरी नजर आईं। हमने देखा कि किस तरह से संक्रमण से बचाव और उससे निपटने जैसे कामों में स्वास्थ्यकर्मियों को लगाया गया। उन्हें अपनी नियमित जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया, जिस कारण उन सेवाओं में स्वास्थ्यकर्मियों की कमी हो गई। इसी तरह, कोरोना मरीजों की जांच और इलाज के लिए स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी सुविधाएं इस्तेमाल की जाने लगीं, जिससे नियमित सेवाएं उन सुविधाओं से महरूम हो गईं। आपूर्ति श्रृंखला लॉकडाउन की वजह से बाधित हो ही गई थी। इन सभी से नियमित स्वास्थ्य सेवाएं, जैसे नियमित टीकाकरण, टीबी के मरीजों की जांच व इलाज, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य देखभाल और पोषण संबंधी कार्यक्रमों में खासा रुकावट पैदा हुई। पर भारत के लिए नवाचार कोई नई घटना नहीं है। महामारी के कुछ महीनों में ही ऐसे कई प्रयोग हुए, जो स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े लोगों की कुछ समस्याओं को हल करते दिखे। कम से कम चार मामलों में खासा नवाचार हुए। पहला मामला है, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना। दूसरा, सामुदायिक (सोशल) मंचों का फायदा लेना। तीसरा, अग्रिम पंक्ति के कर्मियों को सशक्त बनाना और चौथा, आपूर्ति श्रृंखलाओं में बढ़ोतरी करना। ज्यादातर नवाचारों में डिजिटल प्लेटफॉर्म का लाभ उठाया गया। जैसे, सुदूर इलाकों में ऑनलाइन काउंसिलिंग की गई और लोगों को परामर्श दिए गए, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में गंभीर रूप से कुपोषित बच्चों की निगरानी के लिए बाल विकास-निगरानी एप बनाया गया। उत्तर प्रदेश में नियमित टीकाकरण के बारे में लाभार्थी समाज के लिए 'रिमांइडर कॉल' की व्यवस्था की गई। गुजरात, केरल और पंजाब में अग्रिम मोर्चे के स्वास्थ्यकर्मियों के लिए टीबी व कोविड से जुड़े डिजिटल निगरानी एप तैयार किए गए। छाती का स्कैन करने व गड़बड़ियों का पता लगाने के लिए कृत्रिम-बुद्धिमता, यानी एआई आधारित जांच की व्यवस्था की गई। विभिन्न संगठनों ने अग्रिम मोर्चे के अपने कर्मचारियों के प्रशिक्षण और उन तक सूचना आदि पहुंचाने के लिए डिजिटिल मंचों का इस्तेमाल किया। इस तरह की अनेक सेवाएं शुरू की गईं, जिनमें ई-संजीवनी, स्वस्थ, प्रैक्टो, पोर्टिया, टेको, अनमोल जैसे नाम प्रमुख हैं।

खेती-किसानी और किसानों की बेहतरी के पुरोधा शिवराज

किसान पुत्र होने के नाते खेती-किसानी को बेहतर तरीके से जानने वाले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के किसानों के लिए जो किया है, वह कृषि क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हो रहा है। एक लंबे समय से उनके द्वारा खेती-किसानी और किसानों की बेहतरी के लिए किए गए प्रयासों और नवाचारों के परिणाम अब न केवल पूरे देश-दुनिया के सामने है बल्कि उन्हें इसका पुरोधा भी माना गया है। प्रदेश के किसानों के हित में खेती को लाभप्रद बनाने और किसानों की आय दोगुनी करने के लिये मुख्यमंत्री ने अनेक नवाचार भी किए हैं। आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण में कृषि क्षेत्र की महत्वपूर्ण भागीदारी है। कृषि उत्पादन को बढ़ाना, उत्पादन की लागत को कम करना, कृषि उपज के उचित दाम दिलाना और प्राकृतिक आपदा या अन्य स्थिति में उपज को हुए नुकसान में किसान को पर्याप्त क्षतिपूर्ति देना, मुख्यमंत्री के प्रयासों में शामिल हैं। चौहान ने प्रदेश के किसानों को जो संबल दिया, उससे किसानों ने प्रमुख रूप से गेहूं उत्पादन में रिकार्ड कायम किया। मध्यप्रदेश गेहूं उपार्जन में पूरे देश में अव्वल रहा। किसानों के हित में कृषि उपज मंडी अधिनियम में संशोधन करते हुए ई-ट्रेडिंग का प्रावधान किया गया और किसानों को उपार्जन केन्द्र के साथ ही मंडी के अधिकृत निजी खरीदी केन्द्र और सौदा-पत्रक व्यवस्था के माध्यम से भी फसल बेचने की सुविधा प्रदान की गई। गेहूं, धान एवं अन्य फसलों के उपार्जन की 33 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई। प्रदेश के किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में प्रतिवर्ष 6-6 हजार रुपए तो मिल ही रहे हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने प्रदेश के किसानों के लिए मुख्यमंत्री किसान-कल्याण सम्मान निधि योजना की शुरुआत कर किसानों को मध्यप्रदेश शासन की ओर से प्रतिवर्ष 4 हजार दो बराबर किश्तों में दिए जाना शुरू किया गया। इस प्रकार किसानों को अब कुल 10 हजार रुपए प्रतिवर्ष किसान सम्मान निधि मिल रही है। किसानों की परेशानियों को भी चौहान भलीभांति समझते हैं। उन्होंने प्राकृतिक आपदा या किसी अन्य परिस्थिति में किसान की उपज को हुए नुकसान में राहत पहुंचाने वाली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लंबित प्रीमियम जमा कर किसानों को राहत पहुंचाई। लॉकडाउन की विकट स्थिति में एक करोड़ 29 लाख टन गेहूं 16 लाख किसानों से खरीद कर उनके खातों में 27 हजार करोड़ से अधिक की राशि अंतरित किया जाना किसानों के लिये बड़ी राहत थी। मुख्यमंत्री चौहान ने किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज पर ऋण योजना को पुनः चालू करते हुए किसानों को राहत पहुंचाई। इसके लिए सहकारी बैंकों को 800 करोड़ की राशि भी उपलब्ध करवाई गई। किसानों की आय को बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री ने बेहतर प्रबंधन और सिंचाई परियोजनाओं पर प्राथमिकता से कार्य करवाए। इन कार्यों से प्रदेश में अधिक से अधिक क्षेत्र में सिंचाई की उपलब्धता सुनिश्चित की गई। वर्ष 2020 तक लगभग 40 लाख 27 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधाएं विकसित की गईं। प्रदेश में 19 वृहद, 97 मध्यम और 5344 लघु सिंचाई योजनाओं का कार्य पूर्ण किया गया। इसके साथ ही 27 वृहद, 47 मध्यम और 287 लघु सिंचाई योजनाएं प्रगति पर हैं। प्रदेश में अगले 5 वर्षों में 65 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। कोरोना काल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं में 57 हजार 653 जल- संरचनाओं का निर्माण किया गया। इन सभी जल संरचनाओं से जहाँ एक ओर स्थानीय लोगों को कोरोना काल में रोजगार मिला, वहीं भू-जल स्तर में बढ़ोत्तरी के साथ किसानों को खेती में सिंचाई के लिए पानी भी मिल रहा है। प्रदेश सरकार द्वारा विगत कई वर्षों से सिंचाई बजट में निरंतर वृद्धि भी की जा रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंत्रि-परिषद की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राजस्व पुस्तक परिपत्र में नए प्रावधान जोड़े हैं। इन प्रावधानों में प्राकृतिक प्रकोप, आग लगने तथा वन्य प्राणियों द्वारा मकान नष्ट किए जाने पर आर्थिक सहायता को शामिल किया। किसानों को कृषि कार्य के लिए फ्लैट दरों पर बिजली दी जा रही है, जिसमें 22 लाख कृषि उपभोक्ता लाभान्वित हुए हैं। किसानों को खेती के लिए बिजली कनेक्शनों पर 14 हजार 244 करोड़ का अनुदान दिया गया। प्रदेश कृषि अधोसंरचना विकास फंड के उपयोग में मध्यप्रदेश देश में सबसे आगे है। अधोसंरचना विकास के लिए आत्म-निर्भर कृषि मिशन का गठन किया गया है। कृषि विकास एवं किसान-कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं पर 83 हजार करोड़ रुपए से अधिक के हितलाभ दिए गए हैं।

कृषि विज्ञानिकों की मदद से गर्मी में उगाएं नकदी फसलें

मार्च में 10 फसलों की बोवनी से कमा सकते हैं भरपूर मुनाफा

भोपाल, संवाददाता। किसानों की सुविधा के लिए हम हर माह, महीने के हिसाब से फसलों की बोवनी की जानकारी देते हैं। जिससे किसान सही समय पर फसल की बोवनी कर बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकें। इसी क्रम में हम मार्च माह में बोई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ उनकी अधिक उत्पादन देने वाली किस्मों से भी किसानों को अवगत करा रहे हैं, ताकि किसान अपने क्षेत्र के अनुकूल रहने वाली उन्नत किस्मों का चयन करके उत्पादन को बढ़ा सकें। आशा है कि हमारे द्वारा दी जा रही ये जानकारी किसान भाइयों के लिए फायदेमंद साबित होगी। तो आइए जानते हैं मार्च माह में बोई जाने वाली फसलों के बारे में-

अरहर: सिंचित अवस्था में अरहर की टी-21, यूपीएएस 120 किस्में मार्च में लगाई जा सकती हैं। इसके लिए अच्छे जल निकाल वाली दोमट से हल्की दोमट मिट्टी में दोहरी जुताई करके खरपतवार निकाल लें। 1/3 बोरा यूरिया व 2 बोरे सिंगल सुपर फास्फेट डालकर सुहागा लगा दें। अरहर का 7-6 किग्रा स्वस्थ्य बीज लेकर राइजोवियम जैव खाद से उपचारित करके 16 इंच दूर लाइनों में बोवनी करें। अरहर की 2 लाइनों के बीच यदि बैसाखी मूग लगाना है तो दूरी 20 इंच कर लें। बीजाई के 27 और 47 दिन बाद खरपतवारों की रोकथाम के लिए निराई-गुड़ाई करें। हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं।

आलू: पहाड़ी क्षेत्रों में आलू लगाने के लिए झुलसा रोग-रोधक कुफरी ज्योति किस्म उपयुक्त है। अच्छे जल निकाल वाली दोमट मिट्टी में बीजाई के समय एक लीटर क्लोरपाइरीफास 27 ईसी को 10 किग्रा रेत में मिलाकर डालने से दीमक से सुरक्षा रहती हैं। आलू के 10-12 क्विंटल मध्यम आकार के 2-3 आंख वाले टुकड़ों को 0.27 प्रतिशत एमीसान 6 के घोल में 6 घंटों तक डुबोएं। बीजाई के समय काफी नमी होनी चाहिए। वहीं खेत तैयार करते समय 10 टन कम्पोस्ट, 1 बोरा यूरिया, 2 बोरे डी ए पी तथा 1 बोरा पोटशियम सल्फेट 10 इंच दूर कूड़ों में डालकर मिट्टी से ढक दें फिर उपर बीज आलू के टुकडे 8 इंच की दूरी रखकर मिट्टी से ढक दें।

अदरक: मार्च माह में अदरक के 7 किग्रा स्वस्थ कंदों को 18 ईंच लाइनों में तथा 12 इंच पौधों में दूरी रखकर लगाएं। खेत तैयारी पर 10 टन कम्पोस्ट, एक बोरा यूरिया, एक बोरा डीएपी व एक बोरा पोटाशियम सल्फेट डालें। दो महिने बाद एक बोरा यूरिया गुडाई के समय दें।

मशरूम: मशरूम उगाने के लिए हल्के भीगे साफ गेहूं के भूसे या धान के पुआल में खुम्भ के बीज डालने से 3-4 सप्ताह बाद खुम्भ तोड़ने लायक हो जाते हैं। मशरूम उगाना बहुत आसान है। काफी आमदनी देती हैं।

बसंतकालीन गन्ना: बसंतकालीन गन्ना मार्च अंत तक बोया जा सकता है। गन्ने में शुरू में बढ़ोत्तरी धीमी होती है इसका लाभ उठाते हुए 2 लाइनों के बीच एक लाइन अल्प अवधि वाली वैशाखी मूंग, उर्द, लोबिया, मिंडी इत्यादि की मिश्रित फसल लगा सकते हैं, जिनके लिए अतिरिक्त खाद डालनी पड़ेगी। इससे अतिरिक्त फसल तो मिलती ही है।

आंवला: आंवले के लिए कांचन, कृष्णा, नरेन्द्र आंवला-6, नरेन्द्र आंवला-7, नरेन्द्र आंवला-10 यह किस्में लगाई जा सकती है। बीज को बोने से 12 घंटे पहले पानी में भिगो देना चाहिए। जो बीज पानी में तैरने लगे उन बीजों को फेंक देना चाहिए।

चारा वाली 4 फसलें

ज्वार: ज्वार की उजे एस 20, एच सी 136, एच एसी 171, एच सी 260, एच सी 308 किस्में 1510-200 क्विंटल हरा चारा देती हैं। इनके 17 किग्रा बीज को 10 इंच दूर लाइनों में लगाएं।

बाजरा: बाजरा की कोई भी किस्म के 3-4 किग्रा बीज को 12 इंच दूर लाइनों में बोयें इससे 70-77 दिन बाद 160 क्विंटल हरा चारा प्राप्त हो जाता हैं। दोनों फसलों में बीजाई के समय 1 बोरा यूरिया डालें तथा 1 महीने बाद आधा बोरा यूरिया और डाल दें। रेतीली मिट्टी में 1 बोरा सिंगल सुपर फासफेट भी बीजाई पर डालें।

लोबिया: लोबिया की एफओएस 1, न. 10, एच एफ सी 42-1, सी एस 88 किस्में 100-170 क्विंटल हरा चारा 2 महिनों में देती हैं। इनका 16-20 किग्रा बीज को राइजोवियम जैव खाद से उपचारित करने के बाद 12 इंच दूर लाइनों बोयें। बीजाई पर आधा बोरा यूरिया तथा 3 बोरे सिंगल सुपर फासफेट डालें।

हाथी घास: संकर हाथी घास की नेपियर बाजरा संकर-21 किस्म सारा साल हरा चारा देती हैं। इसे जड़ों या तनों के टुकुडों द्वारा उगाया जाता हैं। 20 इंच लम्बे 2-3 गाठों वाले 11000 टुकड़े प्रति एकड़ लगते हैं। आधा टुकड़ा जमीन में तथा आधा हवा में रखकर 30 इंच लाइनों में तथा 24 ईंच पौधे में दूरी रखें। रोपाई से पहले खेते में 20 गाड़ी सड़े-गले गोबर की खाद दें। हर कटाई के बाद 1 बोरा यूरिया डालें। गर्मियों में 10-17 दिन के अन्तर पर सिंचाई करते रहें।

बाजरा की खेती: नई किस्म की विशेषताएं करेंगी किसानों की प्रेरित

कृषि वैज्ञानिकों ने विकसित की अधिक उत्पादन देने वाली नई किस्म

संवाददाता, भोपाल

भारत में बाजरा सर्दियों के दिनों में खाए जाने वाला खाद्यान्न हैं। गेहूं की तरह ही बाजरे की रोटी, चूरमा आदि बनाकर खाया जाता है। भारत में इसकी खेती प्राचीन समय से होती आ रही है। इसकी खेती से दो लाभ हैं। इसकी खेती करने से एक ओर खाने के लिए बाजारा दाना प्राप्त हो जाता है। वहीं पशुओं के लिए भी सूखा चारा मिल जाता है। इस प्रकार किसानों के लिए बाजारा की फसल उगाना काफी फायदेमंद है। किसानों को इस फसल का बेहतर उत्पादन मिल सके इसके लिए चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार के वैज्ञानिकों ने एचएचबी-311 नामक बाजरे की नई बायोफोर्टीफाइड किस्म विकसित की है। इस किस्म को कृषि महाविद्यालय के आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग के बाजरा अनुभाग के वैज्ञानिकों ने विकसित किया है।

कुपोषण का होगा खात्मा: बायोफोर्टीफाइड किस्में वे होती हैं जिसमें पौष्टिक पदार्थ- जैसे प्रोटीन, आयरन, जिंक आदि अधिक मात्रा में होते हैं इन्हें बॉयोफोर्टीफाइड वैरायटी कहा जाता है। पौष्टिक गुणों से भरपूर होने के कारण ये फसल कुपोषण से लड़ने में समक्ष है। इसी कारण वर्तमान में दुनियाभर में बाजरा और बाजरा उत्पादों की मांग लगातार बढ़ती जा रही है।

बाजरा के पोषक तत्व स्वास्थ्य के लिए उत्तम: बाजरे में मुख्य रूप से 12.8 प्रतिशत प्रोटीन, 4.8 ग्राम वसा, 2.3 ग्राम रेशे, 67 ग्राम कार्बोहाइड्रेट एवं खनिज तत्व जैसे कैल्शियम-16 मिली ग्राम, लौह-6 मिली ग्राम, मैग्नीशियम-228 मिली ग्राम, फॉस्फोरस-570 मिली ग्राम, सोडियम-10 मिली ग्राम, जिंक 3.4 मिली ग्राम, पोटैशियम 390 मिली ग्राम व कॉपर-1.5 मिली ग्राम पाया जाता है। इसमें गेहूं एवं चावल से अधिक आवश्यक एमिनो अम्ल पाए जाते हैं। बाजरे के दानों का सेवन सूजन रोधी, उच्च रक्तचाप रोधी, कैंसर रोधी होता है एवं इसमें पाए जाने वाले एंटीऑक्सीडेंट यौगिक हृदयाघात के जोखिम एवं आंत्र के सूजन को कम करने में मदद करते हैं।

पोषक तत्वों की मात्रा ज्यादा: एचएचबी-311 बाजार की किस्म में पोषक तत्वों की मात्रा बाजरा की अन्य किस्मों के मुकाबले अधिक है। इसमें लौह तत्व एवं जिंक क्रमशः 83 व 42 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम पाया जाता है। सामान्य किस्मों में इनकी मात्रा क्रमशः 45-55 व 20-25 मिलीग्राम प्रति किलोग्राम होती है।

नई किस्म की विशेषताएं : यह किस्म जोगिया रोगरोधी है व अन्य किस्मों की तुलना में सूखा चारा व उपज अधिक देने की क्षमता है। यह 75 से 80 दिनों में पककर तैयार हो जाती है। अच्छा रखरखाव करने पर एचएचबी 311 किस्म 18.0 क्विंटल प्रति एकड़ तक पैदावार देने की क्षमता रखती है। बाजरा में गेहूं, धान, मक्का एवं ज्वार की तुलना में शुष्क एवं निम्न उपजाऊ क्षमता, उच्च लवण युक्त भूमि एवं उच्च तापमान के प्रति अधिक प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है।

इन राज्यों में एचएचबी 311 की खेती: अनुसंधान निदेशक डॉ. एसके सहरावत ने मीडिया को बताया कि इनकी उच्च अनाज और उपजाऊ क्षमता व लौह तत्व की मात्रा और रोग प्रतिरोधिकता को ध्यान में रखते हुए एचएचबी-311 को राष्ट्रीय स्तर पर खेती के लिए इसकी सिफारिश की गई है। इसके तहत जोन-ए जिसमें राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब और दिल्ली और जोन-बी में महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए खरीफ सीजन के लिए इसकी सिफारिश की गई है।

विकसित बाजरे की अन्य उन्नत किस्में: बाजरा की नई किस्म एचएचबी 311 इसके अलावा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एचएचबी 223, एचएचबी 197, एचएचबी 67 (संशोधित), एचएचबी-226, एचएचबी 234, एचएचबी 272 किस्में भी विकसित की हैं।

आधुनिक खेती के जरिए किसान बदल सकते हैं तकदीर

भारतीय काजू: मूंगफली की खेती से ज्यादा फायदेमंद

संवाददाता, भोपाल

तिलहन फसलों में मूंगफली का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। मूंगफली के दाने और उनसे निकाला गया तेल दोनों की ही बाजार में अच्छी मांग रहती है। मूंगफली वानस्पतिक प्रोटीन का एक सस्ता स्त्रोत हैं। इसमें प्रोटीन की मात्रा मांस की तुलना में 1.3 गुना, अंडों से 2.5 गुना एवं फलों से 8 गुना अधिक होती है। मूंगफली के बीज में 45 प्रतिशत तेल तथा 26 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा पायी जाती है। जो हमारे शरीर के लिए काफी लाभदायी होते हैं। मूंगफली को भारतीय काजू भी कहा जाता है। सर्दियों में लोग इसे सेक कर खाना पसंद करते हैं। वहीं व्रत या उपवास में भी इसे खाया जाता है। भारत में मूंगफली के उत्पादन का लगभग 75 से 85 प्रतिशत हिस्सा तेल के रूप में इस्तेमाल होता है। अब बात करें इसकी खेती की तो मूंगफली उष्णकटिबंधीय पौधा है। इसकी खेती रबी, खरीफ व जायद तीनों में की जा सकती है। तिलहनी फसलों के मुकाबले मूंगफली एक ऐसी फसल है, जो भारत के 40 प्रतिशत क्षेत्र में उगाई जाती है। यह गुजरात, आन्ध्र प्रदेश, तमिलनाडू और कर्नाटक राज्यों में सबसे अधिक उगाई जाती है। इसके अलावा मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश, राजस्थान और पंजाब में भी इसकी खेती की जाती है।

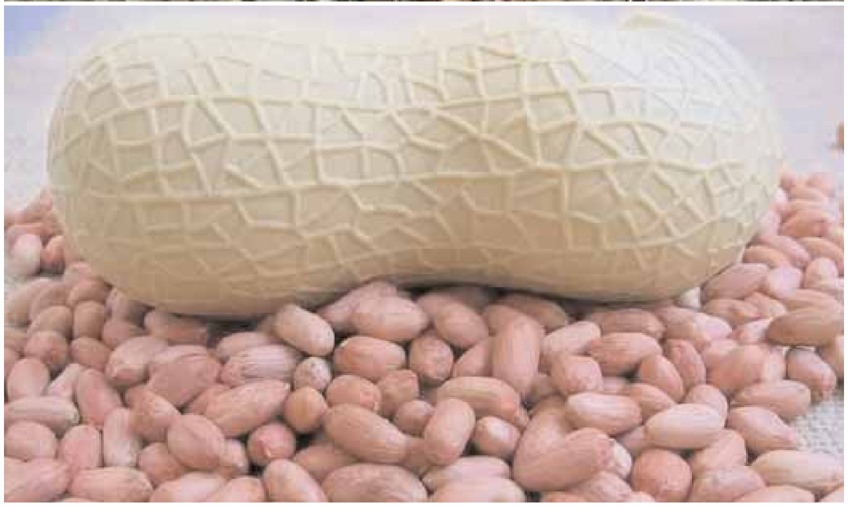

भूमि एवं जलवायु

वैसे तो इसकी खेती अच्छे जल निकास वाली सभी प्रकार की मिट्टी में की जा सकती है। लेकिन मूंगफली की खेती के लिये दोमट, बलुआर दोमट या हल्की दोमट मिट्टी उपयुक्त रहती है। मूंगफली के लिए हल्की अम्लीय भूमि जिसका पी एच मान 6.0 से 6.5 के बीच हो, अच्छी रहती है। वहीं मूंगफली की खेती के लिए भारी दोमट मिट्टी का चयन नहीं करें। मूंगफली की फसल के लिए अर्द्ध उष्ण जलवायु उत्तम है। फसल की अच्छी पैदावार के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान तथा 500 से 1000 मिलीमीटर वर्षा को अच्छा माना गया है।

खेत की तैयारी

मूंगफली की बोवनी करने से पहले खेत की अच्छी तरह से दो से तीन जुताई कल्टीवेटर से करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें। इसके बाद पाटा लगाकर खेत को समतल कर लें। अब बुवाई के लिए कम अवधि में पकने वाली गुच्छेदार प्रजातियों का चयन करें जिसमें डीएच 86, आर-9251, आर 8808 आदि किस्मों का चयन किया जा सकता है। ध्यान रखें बीज का चयन रोग रहित उगाई गई फसल से करें। ग्रीष्मकालीन मूंगफली के लिए 95-100 किग्रा की दर से बीज दर प्रति हेक्टेयर उपयोग करें।

बोवनी का तरीका

जायद मूंगफली की बोवनी 5 मार्च से 15 मार्च तक कर लेनी चाहिए। देरी से बोवनी करने पर बारिश शुरू होने की स्थिति में खुदाई के बाद इसकी फलियों के सूखने की समस्या रहती है। बोवनी से पहले बीजों को उपचारित किया जाना बेहद जरूरी है। इससे फसल में कीट व बीमारियां कम लगती है। मूंगफली के बीज को बोने से पूर्व थायरम 2 ग्राम+ कार्बेन्डाजिम 1 ग्राम प्रति किलो बीज दर से उपचारित कर लें। फफूंदीनाशक दवा से उपचार के बाद 1 पैकेट राइजोबियम कल्चर को 10 किग्रा बीज में मिलाकर उपचार कर लें। इसके बाद खेत में पर्याप्त नमी के लिये पलेवा देकर जायद में मूंगफली की बोवनी करें। यदि खेत में नमी उचित नहीं होगी तो मूंगफली का जमाव अच्छा नहीं होगा।

खाद एवं उर्वरक

यूरिया 45 किलो, सिंगल सुपर फास्फेट 150 किलो व म्यूरेट ऑफ पोटाश 60 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। मूंगफली में नत्रजन की अधिक मात्रा का उपयोग न करें अन्यथा यह मूंगफली की पकने की अवधि बढ़ा देगा।

खुदाई और भंडारण

मूंगफली में जब पुरानी पत्तियां पीली पडक़र झड़ने लगें, फली का छिलका कठोर हो जाए, फली के अंदर बीज के ऊपर की परत गहरे गुलाबी या लाल रंग की हो जाए तथा बीज भी कठोर हो जाए तो मूंगफली की कटाई कर लेनी चाहिए। कटाई के बाद पौधों को सुखाएं और बाद में फलियां अलग करें। फलियों को अलग करने के बाद फिर से सुखाएं ताकि उनमें नमी की मात्रा 8 प्रतिशत रह जाए। फसल की कटाई में देरी होने से फसल का पैदावार और गुणवत्ता दोनों पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए समय पर इसकी कटाई कर लेनी चाहिए।

कब-कब करें सिंचाई

पलेवा देकर बोवनी करें। इसके बाद पहली सिंचाई 20 दिन बाद करें। दूसरी सिंचाई 30-35 दिन पर तीसरी सिंचाई 50-55 दिन पर करें। रबी या जायद मौसम की फसल में 10 से 15 दिन के अन्तराल पर आवश्यकतानुसार फसल की सिंचाई की जा सकती है। जहां पानी की कमी हो वहां पर फूल आने, नस्से बैठते समय, फूल बनते समय तथा दाना बनते समय फसल की सिंचाई अवश्य करनी चाहिए।

ध्यान रखने वाली बातें

- किस्मों तथा मौसम के अनुसार खेत में पौधों की संख्या में अंतर रखा जाता है।
- पंक्ति से पंक्ति की दूरी 30 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें।
- फैलने वाली किस्मों में दूरी 45 से 60 सेंमी और पौधे से दूरी 10 से 15 सेंमी रखें।
- रबी या जायद मौसम में खरीफ मौसम की तुलना में पौधों की अधिक संख्या रखें।
- मूंगफली की बोवनी सीड ड्रिल द्वारा करनी उपयोगी रहती है।
- यदि संभव हो तो किसान मूंगफली की बोवनी मेंड़ों पर करें।
- बीज की बोवनी 4 से 6 सेंमी की गहराई पर करनी चाहिए।

पैदावार व लाभ

मूंगफली की खेती की उन्नत तकनीकों को अपनाकर मूंगफली की खरीफ की फसल से 18 से 25 क्विंटल और रबी या जायद की फसल से 20 से 35 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पैदावार प्राप्त की जा सकती है। अब बात करें इसकी विक्रय से होने वाले लाभ की तो वर्तमान में देश की विभिन्न मंडियों में मूंगफली का न्यूनतम भाव 3550 रुपए तथा अधिकतम भाव 6512 रुपए प्रति क्विंटल तक चल रहा है।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विवि में आंदोलन की तैयारी

7वां वेतनमान नहीं मिलने से कृषि विज्ञानियों में आक्रोश

संवाददाता, जबलपुर

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक, वैज्ञानिक सातवां वेतनमान न मिलने से नाराज हैं। प्राध्यापक, वैज्ञानिक परिषद के पदाधिकारियों का कहना है कि उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से लेकर भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, कृषि मंत्री कमल पटेल समेत कृषि विभाग के अधिकारियों को लगातार सातवें वेतनमान की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। लेकिन आज तक उनकी मांगें पूरी नहीं हो पाईं। प्राध्यापक, वैज्ञानिक परिषद के पदाधिकारियों का आरोप है कि उन्हें सातवें वेतनमान ना लगने की वस्तु स्थिति को लगातार बताया गया। बावजूद इसके अभी तक कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक एवं प्राध्यापकों को सातवें वेतनमान से वंचित रखा गया है। जबकि दूसरी ओर अन्य विश्वविद्यालय के प्राध्यापकों को सातवें वेतनमान के अलावा उनकी एरियर्स की तीसरी किस्त भी प्रदान कर दी गई है। इससे नाराज कृषि विश्वविद्यालय के प्राध्यापक वैज्ञानिक परिषद के पदाधिकारियों द्वारा दोबारा मुख्यमंत्री से मिलकर उन्हें इस समस्या से अवगत कराया गया एवं ज्ञापन दिया गया।

आंदोलन की बना रहे रणनीति

सातवां वेतनमान न मिलने से दुखी विश्वविद्यालय के कृषि वैज्ञानिक एवं प्राध्यापकों द्वारा आगामी समय में एक बड़े आंदोलन की रणनीति बना रहे हैं। सरकार तक अपनी बात पहुंचाने कई सभा का आयोजन किया जा रहा है। प्रधापक संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने कहा कि अब समय आ गया है अपनी मांगों के लिए सड़कों पर उतरने का जल्दी है। हम इसको लेकर उग्र आंदोलन करेंगे।

इन्होंने जताई नाराजगी

केंद्रीय वैज्ञानिक-प्राध्यापक परिषद के अध्यक्ष डॉ. एसके पांडे, कोषाध्यक्ष डॉ. केके अग्रवाल, प्रचार सचिव डॉ. शेखर सिंह बघेल, क्षेत्रीय वैज्ञानिक परिषद के अध्यक्ष डॉ. एमएल केवट, सचिव डॉ. अमित कुमार शर्मा, प्रचार सचिव डॉ. बीएस द्विवेदी, डॉ. अल्पना सिंह एवं विभागाध्यक्ष प्राध्यापक, वैज्ञानिक ने मांग पूरी न होने पर नाराजगी जताई है।

महाकौशल के चित्रकार होंगे **आत्मनिर्भर**

दम तोड़ रहे हथकरघा उद्योगों के अच्छे दिन

रफी अहमद अंसारी, बालाघाट। जिले का हथकरघा उद्योग कभी प्रदेश में अपना अलग मुकाम रखता था, मगर समय की आंधी ने इसे पस्त कर दिया। अब फिर इसमें जान फूंकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फार लोकल मिशन के तहत इसमें नवाचार किया जा रहा है। दम तोड़ रहे हथकरघा उद्योग को संवारने के लिए आदिवासी संस्कृति का सहारा लिया जा रहा है। हथकरघा से बनी साड़ियों में गोंडी चित्रों के नए रंग भरे जा रहे हैं। इससे पहले बाजार में दुपट्टों को भी ऐसे ही चित्रों से सजाकर उतारा गया था। हथकरघा विभाग को उम्मीद है कि साड़ियों को भी लोग हाथोंहाथ लेंगे। इस काम के लिए महाकोशल के बालाघाट, मंडला और डिंडोरी जिले के 50 चित्रकारों का चयन किया गया है।

चित्रकारों को मिलेगा काम: अगर सब ठीक-ठाक रहा तो 350 बुनकर परिवारों को तो संजीवनी मिलेगी ही। बेकार बैठे चित्रकारों को भी काम मिलेगा। दरअसल, बुनकर हथकरघा से सादी साड़ी बनाएंगे। जिस पर चित्रकार गोंडी चित्र बनाकर उसे आकर्षक बनाने का काम करेंगे।

इस तरह तैयार होती है साड़ी: दो दिन में हथकरघा से तैयार हो जाती है। चित्रकारी में आठ दिन लगते हैं। बुनकर को इससे 400-600 रुपए मजदूरी तक मिल जाती है और चित्रकार दो से ढाई हजार रुपए।

रंगीन साड़ी - चार-पांच दिन में हथकरघा से तैयार होती है। चित्रकारी में आठ दिन लगते हैं। बुनकर को 600-1400 रुपए तक मजदूरी मिल जाती है और चित्रकार को दो से ढाई हजार रुपए।

इनका कहना है

हथकरघा विभाग द्वारा शुरू किया नवाचार न केवल बुनकरों के काम को लोगों तक पहुंचाएगा, बल्कि गोंडी कला-संस्कृति को सहेजने के साथ उसे प्रसारित करेगा। बुनकरों के साथ गोंडी चित्रकारों को रोजी-रोजी का नया साधन मिलेगा। सैकड़ों लोग आत्मनिर्भर बनेंगे।

- विनायक मार्को, सहायक संचालक, हथकरघा विभाग, वारासिवनी

पाली हाउस में लगाए 20 हजार पौधे, हर माह कमा रहे एक लाख

गुलाब की खुशबू से महक रहे चंबल के बीहड़

आय के साथ दे रहे आधुनिक खेती का सबक

नीरज शर्मा, भिंड

चंबल का नाम आते ही जेहन में डाकू वाले बीहड़ की छवि सामने आती है, लेकिन वहां अब भी बदलाव की खुशबू है। भिंड शहर के जामना रोड निवासी 40 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव ने पाली हाउस बनाकर डच रोज (गुलाब की एक किस्म) की खेती कर रहे हैं, जिसकी मांग दिल्ली, जयपुर सहित अनेक बड़े शहरों में है। एक साल में चंबल का यह गुलाब देशभर में महका है। प्रशिक्षित कारीगरों के साथ यादव इस प्रयोग से प्रतिमाह एक लाख रुपए तक कमा रहे हैं। वहीं आधुनिक खेती के लिए किसानों को नि:शुल्क प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर भी बना रहे हैं। यादव का कहना है उन्हें बचपन से ही गुलाब पसंद था। तब घर के गमलों में तरह-तरह के गुलाब लगाया करते थे। बाद में जिला उद्यानिकी विभाग से मार्गदर्शन दिया और इसे बतौर व्यवसाय अपना लिया। अगस्त 2019 में जामना रोड पर डेढ़ बीघा जमीन पर पाली हाउस तैयार कराया। पुणे से डच रोज के 20 हजार पौधे मंगाए। तीन माह में ही जनवरी 2020 में इन पौधों में गुलाब आने लगे। दिल्ली, जयपुर, आगरा सहित अन्य बड़े शहरों के फूल व्यापारियों से बात कर सप्लाई शुरू कर दी।

दो दिन में तैयार होते हैं 25 बंच

डेढ़ बीघा जमीन में लगे 20 हजार डच रोज के पौधों से दो दिन में 25 बंच तैयार होते हैं। 20 फूलों का एक बंच होता है। एक फूल की कीमत 20 रुपए तक मिल जाती है। शादी समारोह एवं त्योहारों के समय 25 से 30 रुपये तक बिक जाता है। इस हिसाब से हर माह डेढ़ लाख की बिक्री हो जाती है। फूलों की देखरेख के लिए नियुक्त कर्मचारी, बिजली, पैकिंग से लेकर मंडी तक पहुंचाने का खर्च निकालकर करीब एक लाख रुपये का मुनाफा हर माह होता है।

तीन दिन तक नहीं होते खराब

तोड़ने के बाद तैयार होने वाले बंच में ये फूल तीन दिन तक खराब नहीं होते। इन्हें स्टोरेज करने बाद फूल मंडी में बेचा जाता है। जो लोग पारंपरिक खेती छोड़कर आधुनिक खेती अपनाना चाहते हैं, उनके लिए डच रोज की खेती काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।

इनका कहना है

जिले में एक किसान ने पाली हाउस लगाकर डच रोज की खेती शुरू की है। अन्य किसानों को भी आधुनिक खेती करनी चाहिए। आधुनिक खेती करने के लिए शासन की भी कई योजनाएं हैं। उनके बारे में उद्यानिकी विभाग के कार्यालय में आकर या आनलाइन पता किया जा सकता है।

गंभीर सिंह तोमर, संचालक उद्यानिकी विभाग, भिंड

घर में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने पर मिलेगी 40 प्रतिशत सब्सिडी

छतों का सदुपयोग कर बिल की राशि की जा सकती है कम

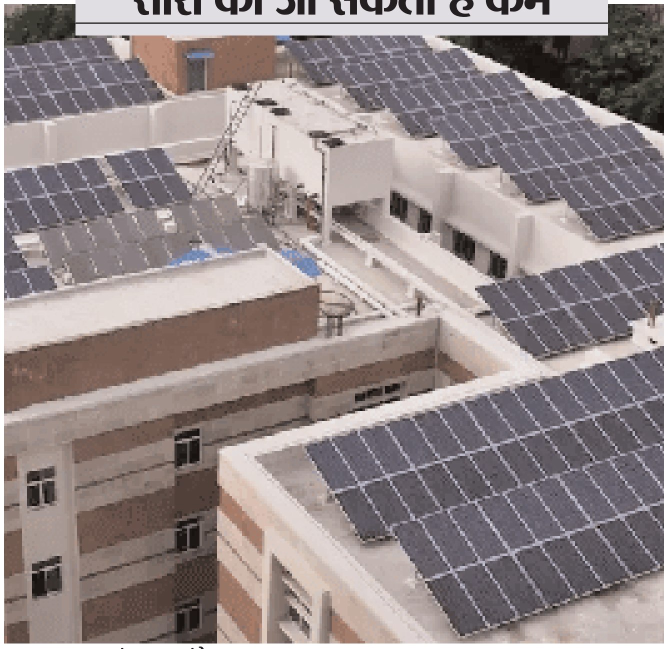

संवाददाता, इंदौर

राज्य सरकार ने नेट मीटरिंग सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने के लिए दूसरे चरण में 40 फीसदी तक सब्सिडी की घोषणा की है। उपभोक्ता अपने घर, बहुमंजिला रहवासी इमारत की छतों का सदुपयोग कर बिजली उत्पादन कर सकते हैं। बिजली कंपनी इन संयंत्रों को नेट मीटरिंग से जोड़ेगी। इससे उनके घर का बिजली बिल भी कम हो जाएगा। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर के मुख्य अभियंता एसएल करवाड़िया ने बताया कि प्रबंध निदेशक अमित तोमर के निर्देशन में कंपनी क्षेत्र में नेट मीटरिंग सौर ऊर्जा को सतत् बढ़ावा दिया जा रहा है। शासन के आदेशानुसार नेट मीटरिंग प्रोत्साहन योजना के दूसरे चरण में 15 मेगावाट के संयंत्र लगाने पर कार्य हो रहा है। इसके लिए इंदौर समेत सभी 15 जिलों में उपभोक्ताओं से घर-घर संपर्क कर योजना की जानकारी दी जा रही है।

पहले से शहर में 850 प्लांट

अभी इंदौर में 850 स्थानों पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगे हैं। बिजली कंपनी ने इन्हें नेट मीटरिंग से जोड़ा है। यानी सौर ऊर्जा से पैदा बिजली की गणना मीटर से की जाती है। उपभोक्ता के बिजली बिल में उतनी यूनिट की छूट दे दी जाती है, जितनी बिजली छत के सौर ऊर्जा संयंत्र से बनाई गई। कंपनी क्षेत्र यानी इंदौर-उज्जैन संभाग में कुल 1750 उपभोक्ता अपनी छतों पर पैनल लगाकर इस्तेमाल से बिजली तैयार कर रहे हैं। कंपनी क्षेत्र में नेट मीटर संयंत्रों की कुल क्षमता 36 मेगावाट से ज्यादा है।

इनका कहना है

नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग के आदेशानुसार 10 किलोवाट क्षमता के घरेलू उपभोक्ताओं को 40 प्रतिशत तक सब्सिडी मिलेगी। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के 500 किलोवाट क्षमता संयंत्र पर 20 फीसदी सब्सिडी प्राप्त होगी। इच्छुक उपभोक्ता मप्र पक्षेविविकं की वेबसाइट या समीप के बिजली वितरण केंद्र, जोन, संभागीय कार्यालय पर संपर्क कर योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

-एसएल करवाड़िया, मुख्य अभियंता, मप्र पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, इंदौर

दतिया में लाखों खर्च फिर भी गौमाता बेघर

गृह मंत्री के जिले में 21 गौशालाएं बनने के बाद भी नहीं मिला आसरा

विनोद पांडेय, दतिया

प्रदेश के गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा के गृह जिला दतिया में 21 गौशालाओं का निर्माण किया गया है, जिनमें तीन गौशालाएं शहरी क्षेत्र में बनाई गई हैं। इसके अलावा 4 निजी गौशालाओं का संचालन कई ट्रस्ट मिलकर कर रहे हैं। शहर में कई गौ-भक्त भी हैं। इसके बावजूद जिम्मेदार नपा इन बेसहारा गायों को सड़क पर घूमने दे रही है। इन गायों से आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। ट्राफिक जाम जैसी स्थिति बनती है। इसी तरह हाईवे 75 पर भी बड़ी मात्रा में गायों के समूह विचरण करते नजर आते हैं, जिनके कारण दुर्घटनाएं होती है। सरकार का लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी संबंधित विभाग से इन गायों को गौशाला पहुंचाने तक का काम नहीं कर पा रहा है। इसमें इन पशु पालकों के खिलाफ कोई चालानी कार्रवाई भी नहीं की जाती है। कई दुर्घटनाओं में गायों की मौत हो जाती है, फिर भी गौ-भक्त मौन हैं। इस तरह गौवंश को लेकर सभी तरफ अव्यवस्थाएं फैली है। शहर में बेसहारा गयों के घूमने का मामला भी बहुत ही अजीब है। पशुपालन विभाग के अनुसार कुल 15,000 पशु शहरी क्षेत्र में हैं। इनमें से 3000 पशु सड़कों पर प्रतिदिन घूमते हैं। दतिया जनपद व नगर पालिका के सर्वे के अनुसार इन पशुओं का कोई मालिक नहीं है।

एक गौशाला को 60 हजार महीना

जिले की सरकारी गौशालाओं को खर्च के लिए प्रत्येक गाय के हिसाब से 20 रुपए प्रतिदिन दिया जाता है। इस तरह 60 हजार रुपए हर महीना एक गौशाला के लिए दिया जा रहा है। यही बजट निजी ट्रस्ट द्वारा संचालित गौशालाओं में भी लागू है। इसके बावजूद लगभग 3000 पशु शहर की सड़कों व नेशनल हाईवे पर घूमते नजर आते हैं, जो दुर्घटनाओं का कारण बन रहे हैं।

नगर पालिका क्षेत्र से बेहतर गांव

दतिया जनपद क्षेत्र में 15 गौशाला हैं और 45 की नई गौशालाओं की मंजूरी मिल गई है। प्रत्येक गौशाला में सौ गाय रखने की क्षमता है। इसी तरह लगभग 1500 पशु ग्रामीण क्षेत्रों में गौशाला में रखे जा रहे हैं। वहीं नगर पालिका क्षेत्र में कोई सरकारी गौशाला नहीं है। चार निजी गौशाला हैं, जहां नगर पालिका के कर्मचारी इन पशुओं को छोड़ देते हैं और कुछ समय बाद यही गौशाला वाले उन्हें वापस सड़कों पर छोड़ देते हैं। सरकारी तौर पर इन गौशालाओं को भारी मात्रा में राशि आवंटित प्रतिवर्ष की जाती है।

इनका कहना है

सरकारी तौर पर हमारे पास कोई गौशाला नहीं है। वहीं 4 गौशालाएं ट्रस्ट संचालित करते हैं। उन्हें सरकारी मदद भी मिलती है, पर वह भी बेसहारा पशुओं को रखने में सहयोग नहीं करते हैं। इस कारण शहर में आवारा पशु घूमते दिखाई देते हैं।

एके दुबे, सीएमओ नपा, दतिया

दतिया जनपद में 15 गौशाला में वर्तमान में कार्य कर रही है। जहां पर लगभग 1500 पशु हमने रख रखे हैं। 45 गौशालाओं की और स्वीकृति मिल गई है। इन गौशालाओं के निर्माण के बाद ही समस्या पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में शहर की अपेक्षा तुलनात्मक रूप से बेहतर व्यवस्था है।

गिरीराज दुबे, सीईओ जनपद, दतिया

विज्ञानिकों ने विकसित की सोयाबीन की नई किस्म

मप्र की धरती उगलेगी नई प्रजाति का 'सोना'

संवाददाता, भोपाल

सोया प्रदेश मप्र में कृषि वैज्ञानिकों ने सोयाबिन की नई प्रजाति विकसित की है। इस प्रजाति के बीज के इस्तेमाल से किसान मालामाल हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार इस बीज से 1 हेक्टेयर में 7 क्विंटल से अधिक की पैदावार होगी। भारत सरकार आरवीएसएम 2011-35 प्रजाति को राष्ट्रीय स्तर पर अनुमोदित किया है। गौरतलब है कि 2022 तक किसानों की आय दोगना करने के अभियान को सफल बनाने में सरकार के साथ कृषि वैज्ञानिक भी लगे हुए हैं। इसी कड़ी में सोया तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए मुरैना के कृषि वैज्ञानिक डॉ. वीके तिवारी ने 5 साल के अनुसंधान के बाद सोयाबीन की ऐसी प्रजाति विकसित की है जिसमें किसान को एक हेक्टेयर में 32 क्विंटल तक पैदावार (5 से 7 क्विंटल अधिक) और 19 फीसदी तेल मिलेगा।

38 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा

सोयाबीन की आरवीएसएम 2011-35 प्रजाति साल 2015 से 2020 तक गहन अनुसंधान के बाद तैयार की जा सकी है। 98 दिन में पैदावार देने वाली इस प्रजाति को 1994 के बाद फिर से विकसित किया गया है ताकि किसानों को एक हेक्टेयर में 30 से 32 क्विंटल तक पैदावार मिल सके। मालवा के किसान प्रदर्शन के तौर पर 32 क्विंटल तक उत्पादन ले चुके हैं। एक हेक्टेयर में बोवनी के लिए 65 से 70 क्विंटल बीज की जरूरत होगी। नई प्रजाति की विशेषता है कि इसमें 38 प्रतिशत प्रोटीन की मात्रा मिलेगी और 19 फीसदी तक तेल जो पुरानी किस्म से 20 फीसदी ज्यादा है।

हार्वेस्टर से नुकसान नहीं

आरवीएसएम 2011-35 प्रजाति की फसल को हार्वेस्टर से कटवाने पर फलियों का नुकसान नहीं होता। दाना भी सुरक्षित मिलता है, क्योंकि इस प्रजाति की सोयाबीन का पौधा जमीन से 5 से 6 फीट ऊपर होने के कारण हार्वेस्टर इसे सुरक्षित तरीके से काटकर भूसा व दाना को अलग कर देता है।

1994 में विकसित हुई थी जेएस-335 प्रजाति

अभी जवाहर सोयाबीन यानी जेएस-335 प्रजाति की सोयाबीन उगाई जाती है। यह प्रजाति सीहोर में साल 1994 में तैयार की गई थी। इस प्रजाति में रोग लगने से उत्पादन कम आने लगा था जिससे किसानों को नुकसान हो रहा था। इस प्रजाति में एक हेक्टेयर में 20 से 25 क्विंटल पैदावार होती है। वहीं इस प्रजाति में एक क्विंटल सोयाबीन में 16 से 17 लीटर तेल ही निकलता है जबकि नई प्रजाति में एक क्विंटल में करीब 19 लीटर तेल निकलेगा।

किसान लेंगे लाभ

अब देशभर के किसान इसके बीज को अपनाकर सोयाबीन की फसल बड़े पैमाने पर ले पाएं। यलो मोजेक वायरस से सुरक्षित रहने के कारण इस प्रजाति की फसल में तेल का प्रतिशत अच्छा बना रहता है। चारकोल राठ कीटव्याधि से सुरक्षा मिलने के कारण सोयाबीन का पौधा जड़ साइड से सूखता नहीं है। पुरानी प्रजाति 110 से 115 दिन में पककर तैयार होती है।

इनका कहना है

सोयाबीन की आरवीएसएम 2011-35 प्रजाति को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि वह यलो मोजेक वायरस व चारकोल राठ से पूरी तरह सुरक्षित रहे। अनुसंधान के दौरान विपरीत परिस्थितियों में भी इस प्रजाति का उत्पादन मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात व राजस्थान के किसानों ने भरपूर लिया है जबकि पुरानी प्रजाति की फसल कीटव्याधि के कारण नष्ट हो गई। इसलिए इस नई किस्म को सदाबहार प्रजाति के रूप में भी देखा जा रहा है।

■ **डॉ. वीके तिवारी,** वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक, आंचलिक कृषि अनुसंधान केंद्र

सर्दी ने जल्दी छोड़ दिया गेहूं की फसल का साथ

कृषि विज्ञानिकों को उत्पादन में कमी के आसार

इंदौर। मध्यप्रदेश में इस साल मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण गेहूं की उपज संकट में है। सर्दी ने गेहूं की फसल का साथ जल्दी छोड़ दिया। यही कारण है कि इस बार प्रदेश के गेहूं उत्पादन में गिरावट देखी जा रही है। गेहूं की कटाई और गहाई के शुरुआती रुझान बताते हैं कि प्रदेश में गेहूं की पैदावार 15-20 फीसद कम रह सकती है। गिरावट का ज्यादा असर मालवा और निमाड़ में देखा जा रहा है। जिस इलाके में प्रति एकएक 15-16 क्विंटल गेहूं पैदा होता था, वहां इस बार 10-11 क्विंटल पर जाकर पैदावार ठहर गई है। पिछले साल राज्य में गेहूं का उत्पादन 371 लाख टन रहा, लेकिन हालात बताते हैं कि इस बार यह आंकड़ा छू पाना मुश्किल है।

इनका कहना है

गेहूं को ठंड पसंद है, लेकिन इस साल गर्मी 10-15 दिन पहले ही आ गई। साथ ही गेहूं पर इल्ली के अलावा बाली और पत्ते को खाने वाले फंगस का असर भी रहा। तापमान बढ़ने से गेहूं समय से पहले ही पक गया। इसका असर उत्पादकता पर पड़ रहा है। अनुमान है कि इस साल 15-20 प्रतिशत उत्पादन कम होगा।

■ डॉ. एके सिंह, प्रधान वैज्ञानिक,भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के क्षेत्रीय गेहूं अनुसंधान केंद्र

आवश्यकता

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर और मुरैना से प्रकाशित

जागत गांव हमार

कृषि और पंचायत पर आधारित साप्ताहिक समाचार पत्र के लिए जिला, जनपद स्तर पर संवाददाता चाहिए।

संपर्क करें

जबलपुर, प्रवीण नामदेव-9300034195
शहडोल, गोपाल दास बंसल-9131886277
नरसिंहपुर, प्रहलाद कौरव-9926569304
हरदा, राजेन्द्र बिल्लोरे-9425643410
विदिशा, अवधेश दुबे- 9425148554
सागर, अनिल दुबे-9826021098
दमोह, बंटी शर्मा -9131821040
टीकमगढ़, नीरज जैन -9893583522
राजगढ़, गजराज सिंह मीणा -9981462162
मुरैना, अवधेश दण्डोतिया -9425128418
शिवपुरी, खेमराज मौर्य-9425762414
भिण्ड- नीरज शर्मा-9826266571
खरगौन, संजय शर्मा-7694897272
सतना, दीपक गौतम-9923800013
रीवा-धनंजय तिवारी-9425080670
रतलाम, अमित निगम-70007141120
झाबुआ-नोमान खान-8770736925

कार्यालय का पता:- लाजपत भवन प्रथम तल, आईसीआईसीआई बैंक के पास, एमपी नगर, ज़ोन-1, भोपाल, मप्र,
संपर्क करें- 07554064144, 9229497393, 9425048589

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, संपर्क-9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)